प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका संख्या 5276/1998

याचिकाकर्ता श्री ई. सत्यनारायण

बनाम

उत्तरवादी म.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रितु मिश्रा, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता।

श्री अभिषेक सिन्हा, उत्तरवादियों के अधिवक्ता।

आदेश

(8.09.2010 को पारित)

1. यह याचिका उत्तरवादी निगम के प्रबंध निदेशक के दिनांक 21/27 अक्टूबर, 1998 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत 17 जनवरी, 1989 से 20 दिसंबर, 1996 तक की अवधि का बकाया वेतन इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता 17 जनवरी, 1989 से 20 दिसंबर, 1996 की अवधि के दौरान व्यवसाय में लगा हुआ था।
2. इस याचिका में अंतर्गत मुद्दे के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि उत्तरवादी संख्या 1 के अधीन रहते हुए, याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई

थी, जिसके परिणामस्वरूप 17 जनवरी, 1989 को खारिज करने का दंडात्मक आदेश जारी किया गया। इसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 569/89 में चुनौती दी गई थी,जिसका अंतिम रूप से 30 अक्टूबर, 1996 के आदेश द्वारा निराकरण कर दिया गया। दंड आदेश अभिखंडित कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया। जहाँ तक बकाया वेतन का संबंध है, यह आदेश दिया गया कि उत्तरवादी नियोक्ता, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करे और इस मामले की जाँच करे कि बर्खास्तगी की तिथि से लेकर बहाली की तिथि तक की अवधि के दौरान वह कहीं और लाभकारी रूप से कार्यरत था या नहीं और जाँच के परिणाम के आधार पर बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किए जाएँ।

3. इसके बाद, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया और जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता को एक नोटिस दिया गया जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में अपना शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए कि वह लाभकारी नौकरी में नहीं था। इस बीच, जाँच अधिकारी भी बदल दिया गया। जब मामले का अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 2006/1998 दायर करके फिर से न्यायालय का का रुख किया, जिसका अंततः 14.5.1998 के आदेश द्वारा 3 महीने के भीतर आदेश पारित करने के निर्देश के साथ निराकरण किया गया। अंत में, आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि वह बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है क्योंकि यह पाया गया है कि विचाराधीन अवधि के दौरान, वह एक व्यवसाय में लगा हुआ था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. उपरोक्त आदेश और बकाया वेतन से इंकार करने की कार्रवाई की आलोचना करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न तो उचित जाँच की गई और न ही सम्यक सुनवाई की गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि जाँच

अधिकारी की नियुक्ति तो हुई, लेकिन उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया, बल्कि जाँच का पूरा मामला एक निजी जासूसी एजेंसी को सौंप दिया गया, जिसने कुछ जाँच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बकाया वेतन न देने का आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दी कि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता को निजी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तथ्यान्वेषी रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और साथ ही न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लंघन हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को नोटिस देकर बकाया वेतन के संबंध में जाँच करने का निर्देश दिया गया था। तर्क दिया कि मामले को किसी निजी एजेंसी को सौंपने के बजाय, जाँच अधिकारी को स्वयं जाँच करनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि एक निजी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी केवल यही कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने बीमार पिता के कपड़े के व्यवसाय में मदद कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता लाभकारी नौकरी में था और अपने पिता से कोई वेतन प्राप्त कर रहा था। इसलिए, लाभकारी नौकरी का कोई प्रमाण नहीं है और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता उस पूरी अवधि के लिए, जिसके दौरान वह सेवा से बाहर था, अर्थात 17 जनवरी, 1989 से 20 दिसंबर, 1996 तक, पूरे बकाया वेतन का हकदार है।

5. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उचित एवं समुचित जांच की गई थी। याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और उसे अवसर प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई थी और यह सेवा नियमों के किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा शासित नहीं थी, इसलिए, तथ्यान्वेषी जांच, निजी जासूसी एजेंसी के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करना पूरी तरह से स्वीकार्य है। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने स्वयं याचिका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में कहा है कि यह एक विस्तृत जांच नहीं थी, बल्कि लाभकारी रोजगार के संबंध में एक साधारण जांच थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं इस तथ्य पर विवाद नहीं करता है कि वह अपने पिता के साथ कपड़ा व्यवसाय में काम कर रहा था और इसलिए, यह स्पष्ट है कि वह उस अवधि के दौरान कपड़ा व्यवसाय से कमाई कर रहा था जब वह बेरोजगार था। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह अपने आप में उत्तरवादियों द्वारा पिछला वेतन देने से इनकार करने की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय न्यायालय ने यद्यपि लाभकारी रोजगार के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया था, नियोक्ता को पिछला वेतन देने के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करने का विवेकाधिकार दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ यह पता चला कि याचिकाकर्ता अपने पिता के साथ कपड़ा व्यवसाय में काम कर रहा था, नियोक्ता ने पाया कि यह पिछला वेतन देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बकाया वेतन पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जाँच के दौरान एक प्रासंगिक परिस्थिति सामने आई, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कोई विवाद नहीं किया, वह यह है कि वह अपने पिता के साथ कपड़े के व्यवसाय में काम कर रहा था और इसलिए, उस प्रासंगिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता ने अपने विवेकानुसार बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया है। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान याचिका की पोषणीयता के संबंध में एक और आपत्ति उठाई और कहा कि चूँकि वाद कारण का कोई भी भाग छत्तीसगढ़ में उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इस न्यायालय को याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं अन्य बनाम विनेश कुमार भसीन** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तरवादी प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत निवेदन का उत्तर देना आवश्यक है।

यह याचिका वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। मामले के तथ्यों को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वाद-कारण याचिका दायर किए जाने की तिथि को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ही उत्पन्न हुआ था, उत्तरवादियों के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में ऐसी कोई आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं था। राज्य के पुनर्गठन पर, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (जिसे आगे "2000 का अधिनियम" कहा जाएगा) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, यह मामला इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि बदली हुई परिस्थितियों में, उत्तरवादियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति थी, तो उसे लिखित रूप में उठाया जाना चाहिए था ताकि याचिकाकर्ता को उसका खंडन करने का अवसर मिल सके। बहस के दौरान ही उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ऐसी आपत्ति उठाई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2000 के अधिनियम की धारा 30 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मामलों के स्थानांतरण के संबंध में वैधानिक योजना निहित है। किसी भी शपथ पत्र द्वारा समर्थित उचित रूप से गठित अभिवचन में कोई तथ्यात्मक आधार न होने के कारण, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में उठाई गई आपत्ति अस्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार अस्वीकार की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य के पुनर्गठन पर यह याचिका इस न्यायालय में स्थानांतरित की गई, **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (पूर्वोक्त)** के मामले में निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है और लागू नहीं होता।

9. 30 अक्टूबर, 1996 के आदेश द्वारा, 17.1.1989 को पारित याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को अभिखंडित कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया। उत्तरवादी नियोक्ता को नियमों के अनुसार विभागीय जाँच करके कथित कदाचार के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी। जहाँ तक बकाया वेतन का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाए और इस मामले की जाँच की जाए कि क्या याचिकाकर्ता बर्खास्तगी की तिथि से लेकर बहाली की तिथि तक की अवधि के दौरान लाभकारी रूप से कार्यरत था और उस जाँच के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किए जाने आवश्यक थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि नियुक्त जाँच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को नोटिस दिए गए थे और उनसे जानकारी मांगी गई थी। याचिकाकर्ता ने स्वयं दलील दी है कि उसने नोटिस के अनुसार अपना शपथ पत्र और अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। उत्तरवादियों की वापसी से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सूचना देने और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना/उत्तर/शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता, उस अवधि के दौरान जब वह बेरोजगार था और दूरस्थ स्थान पर रहता था, इंडस्ट्रियल आर्मी नामक एक निजी एजेंसी की सेवाएँ ली गईं और नोटिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, प्रमाण पत्र आदि याचिकाकर्ता को अग्रेषित कर दिया गया। उक्त एजेंसी ने याचिकाकर्ता के गृह नगर जाकर पूछताछ की और याचिकाकर्ता के पिता और भाई के बयान भी दर्ज किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता बेरोजगार था, वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने पिता के घर में रहा और कपड़े के व्यवसाय में अपने पिता

की मदद की। याचिकाकर्ता के भाई के बयान से पता चला कि याचिकाकर्ता 1989 से 1996 की अवधि के दौरान पेंडुर्थी में अपने पिता की कपड़े की दुकान में बैठता था और अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय में मदद करता था। याचिकाकर्ता के पिता 1989 से कैंसर से पीड़ित बताए जाते हैं। उक्त जांच एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में पिता, भाई और पड़ोसियों के बयान के साथ-साथ उनके पिता की बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट भी भेजी। एकत्र की गई उपरोक्त सामग्री के प्रकाश में, उत्तरवादी-नियोक्ता ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता व्यवसाय से जुड़ा था और इसलिए पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया गया है।

11. याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि उसने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय में मदद की थी। एजेंसी द्वारा की गई पूछताछ और उसके बाद लिए गए निर्णय पर याचिकाकर्ता की आपत्ति इस दलील पर आधारित है कि पूरी जांच केवल जांच अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और जांच की उक्त रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी विवाद नहीं किया है कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित थे और उसका भाई पहले से ही किसी नौकरी में लगा हुआ था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को उसके पिता द्वारा कोई मासिक पारिश्रमिक दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पिता का व्यवसाय करना यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पास आजीविका का कोई वैकल्पिक स्रोत था और इसे लाभकारी रोजगार का मामला नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के 12 अक्टूबर, 1998 के पत्र (अनुलग्नक प्रदर्श-17) से यह खुलासा हुआ है कि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि जाँच चल रही है और याचिकाकर्ता के पिता और भाई के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। उक्त पत्र में, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जाँच के परिणाम की सूचना नहीं दी गई है और उसने उत्तरवादियों से बकाया वेतन जारी करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12.यह ध्यान देने योग्य है कि नियोक्ता द्वारा की गई जाँच अनिवार्य रूप से न्यायालय के निर्देशानुसार लाभकारी रोज़गार के संबंध में एक तथ्यान्वेषी जाँच थी और यह एक नियमित विभागीय जाँच नहीं थी। उत्तरवादी नियोक्ता द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया और याचिकाकर्ता ने अपना शपथ पत्र, प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किए। इसके बाद, नियोक्ता ने एक एजेंसी द्वारा जाँच कराई और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था।

13.जाँच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मैं नियोक्ता द्वारा एकत्रित सामग्री को केवल इस आधार पर खारिज नहीं करना चाहता कि तथ्यान्वेषी जाँच एक निजी एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी, खासकर जब याचिकाकर्ता को पता चला कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, तो उसने रिपोर्ट की प्रति की कोई विशेष माँग नहीं की, बल्कि प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे परिणाम सूचित करें और बकाया वेतन के संबंध में निर्णय लें तथा आवश्यक आदेश पारित करें। प्रत्युत्तर में भी, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) कि अपनी सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर पुनः नियुक्ति तक की अवधि के दौरान वह अपने पिता के साथ बैठा था तथा उनके कपड़ा व्यवसाय में उनकी सहायता कर रहा था।

(ख) कि उनके पिता 1989 से कैंसर से पीड़ित थे

(ग) कि उसका भाई नौकरी में था और एक स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा था

14.इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या उत्तरवादियों द्वारा जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर पिछला वेतन देने से इनकार करना न्यायसंगत और उचित था। चूँकि जाँच के दौरान एकत्रित अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्य, हालाँकि एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए थे, याचिकाकर्ता द्वारा विवादित नहीं किए गए हैं, इसलिए नियोक्ता के निर्णय में केवल इस

आधार पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि जाँच में कोई त्रुटि थी या जाँच एक निजी एजेंसी द्वारा की गई थी या जाँच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी।

15.अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता का अपने पिता के साथ कपड़ा व्यवसाय में संलग्न होना और उससे जुड़े होना, पिछली मजदूरी देने से इनकार करने का आधार बनाया जा सकता है।

उत्तरवादी नियोक्ता ने याचिकाकर्ता के लाभकारी रोजगार के बारे में इस आधार पर अनुमान लगाया है कि याचिकाकर्ता अपने पिता के साथ कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा था। इस न्यायालय की राय में, नियोक्ता द्वारा प्रायिकताओं की प्रधानता के आधार पर निकाला गया ऐसा अनुमान कि याचिकाकर्ता लाभकारी रोजगार में था क्योंकि वह अपने पिता के साथ कपड़ा व्यवसाय में काम कर रहा था, इतना अपमानजनक या मनमाना नहीं कहा जा सकता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। नियोक्ता द्वारा की गई जांच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो केवल याचिकाकर्ता के लाभकारी रोजगार के एक पहलू से संबंधित थी, उत्तरवादियों के पास उपलब्ध सामग्री से लाभकारी रोजगार का अनुमान निराधार नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर का पैराग्राफ-2 उल्लेखनीय है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"2..... पिता का व्यवसाय करना यह नहीं दर्शाता कि उनके पास आजीविका का कोई वैकल्पिक स्रोत था। इस प्रकार, जाँच एजेंसी द्वारा एकत्रित किया जा सकने वाला एकमात्र साक्ष्य यह था कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मदद कर रहा था। इसे लाभकारी रोज़गार नहीं कहा जा सकता, जिससे कि बकाया वेतन के दावे को खारिज किया जा सके।"

2010:CGHC:10582

यह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकारोक्ति है कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मदद कर रहा था और अपने पिता का व्यवसाय कर रहा था।

<u>उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम एम. नागनगौड़ा (2007 (2) एसएलआर 205)</u> के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लाभकारी रोज़गार में स्व-रोज़गार भी शामिल है। इसलिए, नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायसंगत है कि याचिकाकर्ता अपने पिता के व्यवसाय से उस अवधि के दौरान जुड़ा था जब वह रोज़गार से बाहर था।

16.इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और भले ही नियोक्ता को न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से विभागीय जांच करने का अवसर दिया गया था, नियोक्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया और अध्याय को बंद कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. विचारणीय अंतिम प्रश्न यह है कि क्या एकत्रित सामग्री के आधार पर और यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय में मदद कर रहा था, नियोक्ता द्वारा याचिकाकर्ता को बकाया वेतन की पूरी राशि देने से इनकार करना उचित था। हालाँकि, नियोक्ता का यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता बेरोजगार था, उसने अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग किया और उनकी मदद की, फिर भी बकाया वेतन की पूरी राशि देने से इनकार करना उचित नहीं है। हालांकि सामान्यतः यह न्यायालय उपरोक्त पहलू के संबंध में एक और दूर की जांच का निर्देश देता, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हु रखते हुए कि यह याचिका 1998 से लंबित है और उत्तरवादियों ने न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए नई जांच शुरू नहीं की है, इस

न्यायालय की राय में न्याय तभी पूरा होगा जब उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा।

18. परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का 25 प्रतिशत भुगतान करेंगे।

19. तदनुसार याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही /-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore